Vol 6 Issue 5 Nov 2016 ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2231-5063**

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.org

ISSN: 2231-5063 Impact Factor :4.6052(UIF) Volume - 6 | Issue - 5 | November - 2016

GRT Golden Research Thoughts

भारत–अमेरिका आर्थिक संबंध

डॉ. नेहा निरंजन
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन विभाग ,
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि. सागर (म.प्र.)

सारांश

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंधों के अलावा आर्थिक संबंधों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वास्तव में, आज का विश्व आर्थिक सहयोग के आधार पर ही टिका हुआ है क्योंकि आर्थिक सहयोग ही वह आधार भूमि तैयार करता है जिस पर दो देशों के राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संबंधों की आधारभूत संरचना का निर्धारण होता है।

भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों का विश्लेषण इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमरीका विकसित राष्ट्रों के अग्रणी है जबकि भारत विकासशील देशों में प्रमुख है, जो अपने विकास के लिए विकसित देशों से सहयोग की आवश्यकता है। बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में चीन की बढ़ती ताकत अमरीका के लिए सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में दिखाई दे रही है। अमरीका की आर्थिक मंदी ने जहाँ उसे कुछ कमजोर किया है वही चीन का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। एशिया प्रशांत के क्षेत्रों में उसकी पहुँच को रोकने के लिए आवश्यक है कि अमरीका भारत के साथ सहयोग करे। भारत–अमरीका आर्थिक सहयोग दोनों राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों की महती आवश्यकता है। इन्हीं आर्थिक संबंधों के विकास पर प्रकाश डालना इस शोध–पत्र का उद्देश्य है।

मुख्य बिन्दु – उदारवाद, सुदृढ़ वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था, अंतरनिर्भरता, नव उपनिवेशवाद, 21वीं सदी के लिए दृष्टिकोण : भारत अमरीका संबंध, वार्षिक वृद्धि दर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।

भारत विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विधि के शासन तथा प्रतिनिध्यात्मक सरकार के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। यहाँ एक मजबूत और क्रियाशील प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है। एक राष्ट्र–राज्य के रूप में भारत सैकड़ों जातियों के समूह, धार्मिक सम्प्रदाय और सामाजिक व्यवस्थाओं को प्रस्तुत करता है। अमेरिका के टेक्सास, अलास्का और कैलीफोनिया के संयुक्त क्षेत्र से भी भारत बड़ा है। भारत जन–सांख्यिकीय, भौगोलिक और जलवायु विज्ञान संबंधी क्षेत्रों में भी विश्वास एवं महान राष्ट्र है। इसके पश्चिम में रेगिस्तान, पूर्वोत्तर में घने जंगल है, उत्तर में हिमालय की ऊँची–ऊँची चोटियाँ है तो दक्षिण में विशाल पठार एवं भारत के मध्य में गंगा का उपजाऊ मैदान है।

भारत विश्व में सबसे बड़ा और तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है। पिछले एक दशक का मूल्यांकन करने पर हम पाते है कि 2006 में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 8–9 प्रतिशत रहा। यह वृद्धि दर एशियाई देशों में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी दर है। भारत एशिया में जापान और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की हाल की यह आर्थिक सफलता आमतौर पर इसके आंतरिक और बाह्य कारकों के संयोजन पर आधारित है। आंतरिक रूप से एक श्रृंखला के रूप में भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में ठोस विकास के लिए आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को प्रेरित किया गया है और बाह्य रूप से भारत द्वारा उदारवादी नीतियाँ अपनाने के पश्चात् अब वह एक सुदृढ़ वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था का रूप ले रहा है परिणामस्वरूप भारत में विदेशी मुद्रा का आदान–प्रदान तेजी से हो रहा है जिससे भारत के व्यापार एवं निवेश में बढ़ोत्तरी हुई है।

हाल ही में हुई भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के बावजूद भविष्य की समृद्धि के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा/जैसा कि सबसे पहले, हॉलाकि राष्ट्र निर्माण और सेवा क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि हुई है किन्तु यहाँ रोजगार सृजन अपेक्षाकृत कम हुआ है। दूसरा, इतने वर्षों के अनुभव के

बावजूद कृषि क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि हुई है जबकि आधे से अधिक भारतीय परिवार अभी भी अपनी आय के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत की जनसंख्या के हिसाब से यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन स्तर अपेक्षाकृत निम्न है। तीसरा, भारत के ग्रामीण एवं शहर गरीबों के जीवन स्तर को एक मानक मानकर मुद्रास्फीति में उत्पन्न दबावों को एक उभरती चुनौती (आर्थिक) के रूप में देखा जा रहा है।

लंबे समय से भारत तीन अतिरिक्त बाधाओं से जूझ रहा है जोकि आर्थिक विकास में एक अवरोध का कार्य कर रही है जिनमें बुनियादी ढ़ांचा, नौकरशाही, पर्यावरण असंतुलन है। भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्व से ही अपर्याप्त परिवहन संसाधनों एवं विद्युत आपूर्ति की कमी से जूझ रही है और कछुआ गति से आगे बढ़ रही है।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक संबंधों का महत्व

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में किन्हीं दो देशों के पारस्परिक संबंधों का स्वरूप दो स्तरों पर देखा जाता है, प्रथम राजनैतिक एवं कूटनीतिक संबंधों का स्तर और दूसरा आर्थिक संबंधों पर स्तर। वर्तमान वैदेशिक संबंधों की दुनिया में आर्थिक संबंध प्रमुख हो गये है क्योंकि मुख्य रूप से आर्थिक हित ही कालांतर में किसी देश के राष्ट्रहित बन जाते है। वास्तव में, आज का विश्व आर्थिक सहयोग के आधार पर ही टिका हुआ है क्योंकि आर्थिक सहयोग ही वह आधार भूमि तैयार करता है जिस पर दो देशों के राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संबंधों की आधारभूत संरचना का निर्धारण होता है। इसलिए आर्थिक संबंधों की उपयोगिता असंदिग्ध है।

आर्थिक संबंधों के विश्लेषण से पूर्व हमें विश्व व्यवस्था के स्वरूप को समझना होगा। आज का विश्व मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित है– प्रथम वर्ग में वे राष्ट्र आते है जो आर्थिक रूप में सम्पन्न एवं समृद्ध है जिन्हें विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी राष्ट्र। दूसरे वर्ग में उन नव स्वतंत्र राष्ट्रों को रखा जाता है जो अपने देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पुनर्निर्माण के कार्य में संलग्न है। इस श्रेणी में एशिया एवं अफ्रीका के वे राष्ट्र आते है जिन्हें द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद स्वतंत्रता मिली है जिन्हें विकासशील राष्ट्रों के नाम से संबोधित किया जाता है। तीसरे वर्ग में वे राष्ट्र आते है जो अभी भी उपनिवेशवाद, गृहयुद्ध शोषण और राजनीतिक अत्याचार की विभीषिका से ग्रस्त है। इन देशों को अल्पविकसित राष्ट्रों के नाम से संबोधित किया जाता है। जिनके विकास का दायित्व उन विकसित राष्ट्रों पर है जो आधुनिक जीवन की सभी सुख–सुविधाओं को उपभोग कर रहे है।

भारत–अमेरिका के आर्थिक संबंधों के विश्लेषण के महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए इसलिए और भी अनिवार्य हो जाते है क्योंकि अमेरिका विकसित राष्ट्रों में अग्रणी है। इसके विपरीत, भारत विकासशील राष्ट्रों में प्रमुख है जो अपने सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक मूल आधारों की प्रक्रिया में संलग्न है तथा जिसे हर विकसित देश से सहयोग एवं सद्भावना की आवश्यकता है जो उसे उसकी राजनैतिक मान्यताओं को धूमिल या खण्डित किए बिना सहयोग देने का इच्छुक हो।

आज के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के युग में कोई भी देश अकेले रहकर अपना विकास नहीं कर सकता उसे पारस्परिक सहयोग के 'अंतर्निर्भरता' के सिद्धांत को अपनाना ही होगा। यह सिद्धांत विकसित और विकासशील सभी राष्ट्रों पर लागू होता है अतः विकासशील और अल्पविकसित राष्ट्रों की आर्थिक समृद्धि के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग की महती आवश्यकता है लेकिन प्रश्न यह है कि इन देशों की सहायता का आधार किस प्रकार का हो? क्योंकि आर्थिक सहायता देने वाले राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को संबर्द्धित करने के परिपेक्ष्य में ही सहायता प्रदान करते है ताकि वे सहायता प्राप्तकर्ता देशों की आंतरिक राजनीति व्यवस्था को अपने हित में प्रभावित कर सके। यह प्रश्न विकासशील राष्ट्रों के लिए इसलिए सामयिक और अत्याधिक महत्व हो जाता है क्योंकि आर्थिक सहायता और राजनीतिक व्यवस्था (स्वतंत्रता/संप्रभुता) में तालमेल बैठाना उनके लिए समस्या बन जाता है जबकि दोनों ही उनके अस्तित्व को अक्षुण बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इसी तालमेल की सफलता एवं विफलता पर ही विकासशील राष्ट्रों का भविष्य निर्भर करता है।

यदि देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक नीति का आधार ही अपने सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से संबंधित देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए अपने आर्थिक लक्ष्यों को हस्तगत करना है। इस प्रकार कच्चे माल पर नियंत्रण, बाजार पर एकाधिकार एवं प्रतिबद्ध आर्थिक सहायता जैसे सिद्धांत अमरीकी आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण आधार है। भारत उसकी इस नीति के प्रति सतर्क तो अवश्य रहा है लेकिन वह पूर्णरूप से अमरीका की उपेक्षा भी नहीं कर सकता। पं. जवाहर लाल नेहरू ने अमरीका की आर्थिक नीति पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि ''नये साम्राज्यवादियों ने पुराने साम्राज्यवादियों से काफी कुछ सीखा एवं लाभ अर्जित किया है। उन्होंने परंपरागत साम्राज्यवादी तरीकों का परिमार्जन कर दिया है। वे अब किसी देश को हड़पते नहीं जैसा कि ब्रिटेन ने भारत को हड़पा था, वे अब आर्थिक लाभ को ही अपना केन्द्र बिन्दु मानते है। इसी चातुर्यपूर्ण तरीके को ही ''आर्थिक साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद'' कहते है। यद्यपि मानचित्र स्वतंत्र एवं संप्रभुसा प्रतीत होता है किन्तु यदि परदे के पीछे देखे, तो पायेगें कि देश पूर्णतः सहायता देने वाले राष्ट्र की गिरफ्त में फंस चुका है। यह है एक अदृश्य साम्राज्यवाद जिसका अमेरिका संरक्षक है।''

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद साम्यवाद और पूँजीवाद अर्थात् पूर्व सोवियत संघ और अमरीका के मध्य अपने–अपने प्रभाव को स्थापित करने की जो नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई जिसे हम शीतयुद्ध कहते है, के कारण विकासशील राष्ट्र एवं अल्पविकसित राष्ट्र एक ओर तो लाभान्वित हुए है तो दूसरी ओर उनके राष्ट्रीय हितों को इस प्रतिस्पर्धा में क्षति भी पहुँची है। इसलिए यह स्वभाविक प्रश्न उठता है कि जो आर्थिक सहयोग हमें मिल रहा है क्या वास्तव में इसे हम सहयोग कहेगें? अमेरिका का दावा है कि वह विकासशील देशों की आर्थिक सहायता करता है। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे वह सहायता या सहयोग का नाम देता है, वह एक भ्रम है। क्योंकि अमेरिका सहायता या ऋण देने से पहले एक शर्त लगा देता है कि सहायता प्राप्तकर्ता देश केवल ऋणदाता देश से ही माल खरीद सकते है अन्यत्र जगह से नही। क्या इसे हम सहायता कहेंगे? वस्तुतः सहायता का अर्थ है ''बिना किसी प्रतिबंध या सीमा के ऋण या अनुदान देना। किन्तु वर्तमान में ऐसा संभव नहीं है। इसका उदाहरण हमें वियतनाम युद्ध के समय मिलता है, जब भारत का दृष्टिकोण वियतनाम युद्ध में अमेरिका के प्रतिकूल था उस समय तो अमेरिका ने भारत से यहाँ तक कह दिया था कि भारत को आर्थिक सहायता लेने से पहले अपनी वियतनामी नीति में परिवर्तन करना होगा।'' वास्तव में अमेरिका के लिए 'सहायता देने' का अर्थ है प्राप्तकर्ता देश को अपना पिछलगू बनाना ताकि वे अमेरिका की हां में हां मिलाए। भारत भी इस नीति से अछूता नहीं है। अमेरिका ने जब–जब भारत को आर्थिक सहयोग दिया है तब–तब उससे शर्तें जोड़ी है किन्तु दूसरी ओर भारत भी अपनी गुटनिरपेक्ष नीति पर अडिग रहा है। अतएव यह स्पष्ट है कि अमेरिका आर्थिक मदद करने के बदले मदद

प्राप्तकर्ता देशों से यह अपेक्षा करता है कि वे अपने घरेलू मामलों में उसे हस्ताक्षेप करने देगें। इस दृष्टि से विकासशील देशों की स्थिति चिंतनीय हो जाती है क्योंकि इससे उनकी संप्रभुता और अखण्डता को ही खतरा उत्पन्न हो जाता है लेकिन बिडंबना यह है कि आज विश्व की आर्थिक राजनीति का स्वरूप ही ऐसा है कि अब विकासशील और अल्पविकसित राष्ट्रों के समक्ष दो ही विकल्प है या तो अमेरिकन नीति का समर्थन एवं अनुकरण करे या अनन्य रूप से स्वतंत्र मार्ग अपनाकर अमेरिका का कोपभाजन बने।

1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद आज तक भारत और अमेरिका के बीच, व्यापारिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उतार–चढ़ाव का अनुभव देखने को मिलता है। 1950 एवं 1960 के दशक तक अमेरिका, भारत का एक प्रमुख साझेदार बन गया था जो कि अपने आयात का एक तिहाई हिस्से के बराबर था हालांकि उस समय भारत सोवियत संघ के साथ घनिष्टता बनाये हुये था। जोकि भारत–पाकिस्तान युद्ध 1965 तक रहा अतः अगले 40 वर्षों तक भारत–अमेरिका संबंध शून्य की स्थिति में रहे।

सोवियत संघ के विघटन के बाद आज विश्व में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है जिसका विश्व राजनीति पर वर्चस्व और बढ़ गया है ऐसी स्थिति में भारत की विदेश नीति में अमेरिका के प्रति झुकाव होना स्वाभाविक है। 1990 में भारत द्वारा उदारीकरण की अवधारणा को अपनाने के पश्चात् भारत के साथ आर्थिक संबंधों की स्थापना हेतु अमेरिका की रूचि भी भारत में बढ़ी है इसी परिपेक्ष्य में 1994 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हाराव की अमरीका यात्रा में दोनों के संबंधों में नवीनता आई है।

11 मई 1998 को प्रधानमंत्री अटलबिहारी बाजपेयी के कार्यकाल में भारत ने राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में तीन भूमिगत परमाणु परीक्षण किए, जिसकी न केवल अमरीका अपितु विश्व समुदाय ने भर्त्सना की और भारत के विरूद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। जिससे भारत–अमेरिका संबंधों में पुनः तनाव उत्पन्न हो गया किन्तु 21वीं शताब्दी में एशियाई शक्ति संतुलन में भारत की महत्ता को समझते हुए अमरीका ने पुनः भारत के साथ मधुर संबंध बनाने के प्रयास प्रारंभ कर दिये। मार्च 2000 में अमरीकी राष्ट्रपति बिलक्लिंटन की भारत यात्रा से भविष्य के संबंधों की जो आधारशिला रखी गई और दोनों पक्षों के बीच निरंतर संवाद बनाये रखने के लिए वार्ताओं का जो स्वरूप तैयार किया गया है उससे यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि अब दोनों देशों के बीच सभी मतभेद दूर होंगे और संबंधों में प्रगाढ़ता आयेगी।

वैश्वीकरण के इस युग में भारत एक बड़े विश्व बाजार के रूप में उभरा है जो अमरीकी सामग्रियों की खपत कर सकता है अमेरिकी निवेशकों के लिए भी भारतीय बाजार अनुकूल रहे है। अमेरिका भी इस बात को स्वीकार करता है कि भारत में प्रौद्योगिकी आधारित विकास की असीम संभावनायें है, अमरीका के लिए सबसे अधिक आउटसोर्सिंग भारत से ही होती है भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है और मानवीय संसाधन की दृष्टि से भी भारत सम्पन्न देश है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की संख्या भी लाखों में हैं जो अमरीकी समाज को प्रभावित करते रहते हैं जिसमें अमरीकी सांसदों द्वारा स्थापित 'इण्डिया कॉक्स' की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परमाणु परीक्षण के माध्यम से भारत ने परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र की पहचान प्राप्त कर ली है जिसमें ''नो फर्स्ट यूज – नो फर्दर टेस्ट'' No First Use - No Further Test की घोषणा ने अमरीका को प्रभावित किया है भारत की इस बढ़ती हुई शक्ति एवं एशिया में चीन की बढ़ती हुई ताकत ने भी अमेरिका के लिए भारत के साथ प्रगाढ़ संबंधों की स्थापना को आवश्यक बन दिया है।

21 मार्च 2000 को अमेरिका राष्ट्रपति बिलक्लिंटन द्वारा की गई भारत यात्रा में अमरीकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री ने मिलकर ''21वीं सदी के लिए दृष्टिकोण : भारत–अमरीका संबंध'' शीर्षक से जारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये जिसे 'विजन स्टेटमैन्ट–2000' कहा गया। 21वीं सदी में द्विपक्षीय संबंधों के एक बिलकुल नये दौर की शुरूआत करते हुए भारत और अमरीका ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति, दक्षिण एशिया में तनावों में कमी, आर्थिक एवं सामरिक सहयोग नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम, पर्यावरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर साझा सहमति बनायी गई।

इस ऐतिहासिक यात्रा के बाद दोनों राष्ट्रों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारतीय परमाणु परीक्षण कार्यक्रम के प्रश्न पर भी राष्ट्रपति क्लिंटन ने अपना रूख सकारात्मक करते हुए उसे भारत का आंतरिक मुद्दा माना। भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीयों से पूछा कि परमाणु परीक्षण के पश्चात् भारत की सुरक्षा बढ़ी है अथवा नहीं यह खुद निर्णय करें। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि केवल भारतीय ही जान सकते है कि ''आज वह वास्तव में सुरक्षित है या कि परीक्षण के पहले।'' केवल भारत ही यह निश्चित कर सकता है कि परमाणु शस्त्र बढ़ाने, प्रक्षेपास्त्र क्षमता बढ़ाने आदि से भारत को लाभ होगा . . . ।''

जनवरी 2001 में क्लिंटन को हराते हुए जार्ज डब्लू. बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने वे रिपब्लिक पार्टी के थे। उन्होंने भी भारत के साथ अपने संबंधों की महत्ता को समझते हुए भारत–अमरीका परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु ऐतिहासिक प्रयास किए। अमेरिका के नीति निर्धारण संस्था के नये प्रमुख रिचर्ड हॉस भारत के साथ प्रशासनिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। उन्होंने 'अमेरिका–भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता' के विचार पर खासी रूचि दिखायी। राबर्ट जेलिक ने घोषणा की कि अब अमेरिका भारत से आयात होने वाले 42 सामानों पर कोई आयात शुल्क नहीं लगायेगा। इस तरह के आयात का मूल्य 600 मिलियन डॉलर है।

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है तथा भारत अमरीका का 25वॉ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत–अमेरिका के साथ विदेशी व्यापार में लगातार ऋणात्मक वृद्धि को दर्शाता है अर्थात् भारत निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक करता है। अमेरिका से भारत में आयात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में बहुमूल्य पत्थरें, खाद्य उत्पाद और रासायनिक पदार्थ शामिल है वही भारत को किए जाने वाले अमरीकी निर्यात में मशीनें, परिवहन उपकरण, रसायन आदि वस्तुएँ प्रमुख हैं।

डेविड मल्फोर्ड के अनुसार, ''यदि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्रीय हिस्सेदारी के साथ वैश्विक बाजार में स्थान देता है तो इससे भारत न केवल अपनी जनसंख्या की मांगों की पूर्ति कर सकता है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करके विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता है।''

सितम्बर 2005 में भारतीय वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम ने अमरीकी यात्रा के दौरान आर्थिक क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग पर जोर देते हुए कहा था कि, अन्य विकासशील राष्ट्रों के संबंध में भारत कुछ निश्चित लाभ रखता है क्योंकि इसकी क्षमताएँ, बौद्धिक श्रम अमरीकन ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकता है। अमरीका, भारत में अपने वित्तीय स्त्रोतों को निवेश कर चुका है जबकि भारत ने यू.एस.ए. में मानवीय स्त्रोतों का निवेश किया है। वित्तमंत्री के अनुसार, विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती

है अतः भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अमरीकी जीडीपी जो कि 800 विलियन डॉलर के आसपास है उसका 10 प्रतिशत भारत की जीडीपी में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है . . . भारत के पिछले 25 वर्षों के औसत रिकार्ड में देखा जाए तो 5.8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है। . . . विश्व के पाँच सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों में अमेरिका, जापान, चीन, भारत और जर्मनी है।

2004 के बाद भारत (नई दिल्ली) और वाशिंगटन (अमेरिका) के मध्य तक सामरिक साझेदारी प्रारंभ हुई जिसका मुख्य आधार साझा मूल्यों एवं आर्थिक और व्यापार सुधार संबंध था। भारत तेजी से आर्थिक विकास के क्षेत्र में विस्तार कर रहा है और कई अमेरिकी कंपनियां भारत से आकर्षित होकर बाजार तलाश कर निवेश करना प्रारंभ कर रही थी। भारतीय सरकार 1991 से अपना सतत् प्रयास इस क्षेत्र में करता रहा था जिसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी, खुला व्यापार एवं बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था लाना था। हालांकि अमेरिकी सरकार यह जानती थी कि भारत में आर्थिक सुधारों की गति बहुत धीमी एवं असमान प्रगति की है।

अमेरिका के शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार समझोते के तहत 1966 में जो 10 अरब डॉलर थे जो एक दशक बाद में 2006 में बढ़कर 31 अरब डॉलर हो गये थे। वर्तमान 2016 में यह आंकड़ा 100 अरब डॉलर पहुंच गया। दिसम्बर 2006 को राष्ट्रपति जार्ज डब्लू बुश ने, कानून एचआर–5682 हेनरी जे हाइड, यूनाइटेड स्टेट – भारतीय शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग अधिनियम 2006 पीएल–109–401 पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत के साथ नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त किया गया। अर्थात् इसके अधीन 1954 के अमरीकी परमाणु कानून की धारा 123 के अधीन अमरीकी प्रशासन को यह छूट दे दी कि वह भारत के साथ एक नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग संधि पर समझौते कर सकता है।

भारत–अमेरिका वाणिज्य, व्यापार एवं आर्थिक आयोग के तहत वर्तमान में भारत एवं अमेरिका दोनों राष्ट्रों के उद्यमी एवं व्यापारीगण दोनों राष्ट्रों के मध्य मजबूत एवं उन्नत वाणिज्यिक एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जनवरी 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओवामा एवं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दोनों ने संयुक्त रूप से द्विपक्षीय वाणिज्यिक एवं आर्थिक साझेदारी को अस्तित्व में लाकर दोनों राष्ट्रों के मध्य नये युग की शुरूआत की। फलस्वरूप रणनीतिक वाणिज्यिक संवाद से दोनों राष्ट्रों की सरकारों के माध्यम से अपनी कटिबद्धतायें व्यक्त की साथ ही दोनों राष्ट्रों ने इसकी मद्द से आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन के साथ–साथ मध्यम वर्ग के उत्थान हेतु नीति निर्धारण में सहयोग देने हेतु आपसी सहमति व्यक्त की।

अमेरिकी विदेश सचिव जॉन केरी एवं अमेरिकी वाणिज्य सचिव पेनी रिट्जकर ने भारतीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने संयुक्त वार्ताकर हस्ताक्षर किये। सामरिक एवं वाणिज्य संवाद ने भारत अमरीका के आर्थिक साझेदारी के प्रयासों को बढ़ाया है। अब इस साझेदारी में व्यापार के साथ–साथ शिक्षा, संस्कृति, मित्रता और व्यक्ति विशेा के विकास को भी शामिल किया गया है। जिससे भारत और अमरीका द्विपक्षीय व्यापार जहाँ वर्ष 2000 में 19 विलियन डॉलर था वह 2014 में बढ़कर 100 विलियन डॉलर हो गया है। अमरीका का भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28 विलियन डॉलर पहुँच गया है वही अमरीका में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2014 में 7.8 विलियन डॉलर रहा। 21 सितम्बर 2015 में दोनों राष्ट्रों के कार्यपालन अधिकारियों ने (S&CD) की निगरानी में व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ाने में आपसी सहयोग हेतु वार्तालाप की एवं सीईओ (CEO) फोरम के माध्यम से, निवेश पर व्यापार नीति फोरम (Trade Policy Form) के माध्यम से सूचना एवं संचार तकनीकी कार्यकारी ग्रुप आदि के द्वारा समेकित मेपिंग के माध्यम, निवेश को बढ़ावा देने के माध्यम से दोनों राष्ट्रों ने आपसी सहयोग समृद्ध करने की दिशा में काम करते हुये एक दूसरे के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की। साथ ही भविष्य में दोनों इन्हीं संबंधों पर कायम रहते हुये सहयोग करने हेतु दृढ़ संकल्पित रहेंगे। दोनों राष्ट्रों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की दोनों राष्ट्र स्मार्ट सिटी यातायात, कृषि विकास, तकनीकी एवं नाभकीय इत्यादि मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग देने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दोनों राष्ट्रों के आर्थिक संबंधों में मधुरता बढ़ी है दोनों ने एक दूसरे के प्रति भरोसा जताया है। द्विपक्षीय व्यापार और संबंधों में सुधार में वृद्धि के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच कुछ ऐसे मुद्दे (क्षेत्र बिन्दु) है जिनके अंतर्गत दोनों देशों को एक दूसरे के घरेलू बाजारों में पहुँच की तलाश के रूप में अधिक से अधिक बाजार प्राप्त हो सकते है।

संदर्भ सूची –

1.दीनानाथ वर्मा, भारत और विश्व राजनीति, ज्ञानदा प्रकाशन, 1975, पृ. 238–239
2.यू.आर. घई, भारत की विदेशनीति, न्यू एकेडमिक पब्लिशिंग कंपनी, जालंधर, 2007, पृ.8
3.Jawahar Lal Nehru - "Glimpse of World History", New Delhi, p.478-479.
4.Shadhana Mukherji - "Indias Economic Relations with U.S.A. & U.S.S.R. Sterling Publications, New Delhi, 1978, p.60.
5.For a Broader Discussion of the Bilateral Relationship, See CRS Report RL 33529 India_US Relation, K by Alan Kronstadt.
6."US India Joint Statement" Office of the Press Secretary, The White House, March 2, 2006.
7.US-India Commercial, Trade and Economic Co-operation, Fact Sheet Offect of the Spokesperson, Washington DC, Sept. 2015.

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- ✶ International Scientific Journal Consortium
- ✶ OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org